



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941

No. 512]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/ BHADRA 13, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2019

सं. 29/2019- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 632(अ).—जहां कि “रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पामोलीन और रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम ऑयल” (एतशिमन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतशिमन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद [1511 90 10] या टैरिफ मद [1511 90 20] के अंतर्गत आते हैं, के आयात से संबंधित मामले में व्यापार उपचार महानिदेशालय ने भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2017 (एतशिमन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 9 के अनुसार प्रारंभिक मामला संख्या (SG) 04/2019, दिनांक 14 अगस्त, 2019, जिसे दिनांक 14 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के तहत जांच का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि अधिसूचना (द्विपक्षीय सुरक्षा जांच) वाद संख्या (SG) 04/2019, दिनांक 26 अगस्त, 2019, जिसे दिनांक 26 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा जारी द्विपक्षीय सुरक्षा जांच के प्राथमिक निष्कर्षों में महानिदेशक ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि :-

(क) भारत में विषयगत वस्तु के आयात में काफी वृद्धि हुई है। मलेशिया से उक्त विषयगत वस्तु का आयात 2016-17 के 626,362 मैट्रिक टन से बढ़कर जनवरी से जून, 2019 तक की अवधि में 2,596,225 मैट्रिक टन (वार्षिक आधार पर) हो गया था। इस प्रकार इसमें 314 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है।

(ख) आयात के त्रैमासिक प्रगति से जाहिर होता है कि अक्टूबर-दिसम्बर, 2018 में केवल 27,206 मैट्रिक टन का आयात हुआ था जो कि अप्रैल-जून, 2019 में बढ़कर 804528 मैट्रिक टन हो गया। इस प्रकार इसमें 29 गुना वृद्धि हुई है।

(ग) कीमतों के कम रहने से ऐसे आयात में जो वृद्धि हुई है उससे जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में बहुत अधिक शिथिलता आई है।

(घ) यद्यपि घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता बहुत अधिक है, फिर भी विषयगत वस्तु की घरेलू मांग के बढ़ने के बावजूद ये विषयगत वस्तु के उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं कर सके हैं।

(ङ) बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा बहुत ही कम हो गया है।

और उनका प्रारंभिक निष्कर्ष यह है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियां विद्यमान हैं जिससे कि यदि सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने में विलंब हुआ तो घरेलू उत्पादकों को अपूर्णीय क्षति हो सकती है और उन्होंने भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया में मूलतः उत्पादित विषयगत वस्तु के आयात पर सीमा शुल्क की दर में 180 दिनों के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 जुलाई, 2011, जिसे सा.का.नि. 499 (अ), दिनांक 01 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करके भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया में मूलतः उत्पादित और वहां से आयातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क की दर में 180 दिनों के लिए 5% की वृद्धि करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम संख्या 130 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“130क	151190	सभी वस्तुएं	50.0”;

(ii) सारणी के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 130 में निहित कोई भी बात और उनसे संबंधित प्रविष्टियां 2 मार्च,

2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू नहीं होंगी :

बशर्ते और भी कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 130क में निहित कोई भी बात और उससे संबंधित प्रविष्टियां 03 मार्च, 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होंगी”

[फा. सं. 354/132/2019-टीआरयू]

रूचि विष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 जुलाई, 2011 को सा.का.नि 499(अ), दिनांक 01 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 84/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जिसे सा.का.नि 1259 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 4th September, 2019

No. 29/2019-Customs

G.S.R. 632(E).—Whereas the Directorate General of Trade Remedies in the matter concerning imports of “Refined Bleached Deodorized Palmolein and Refined Bleached Deodorized Palm Oil” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item [1511 90 10] or tariff item [1511 90 20] of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), initiated an investigation in terms of rule 9 of the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) *vide* notice of initiation Case No. (SG) 04/2019, dated the 14th August 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary the dated 14th August 2019.

And Whereas, in the preliminary findings of Bilateral Safeguard Investigation issued *vide* notification (Bilateral Safeguard Investigation) case no (SG) 04/2019, dated the 26th August 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary on 26th August, 2019, the Director General has noted that: -

- (a) the import of subject goods into India has shown significant increase. Imports of subject goods from Malaysia increased from 626,362 MT in 2016-17 to 2,596,225 MT in January-June, 2019 (on annualized basis) thus showing an increase of 314 percent;
- (b) quarterly movement in imports shows that imports were just 27,206 MT in October-December, 2018, which surged to 804528 MT in April-June, 2019 thus showing a surge of almost 29 times increase;
- (c) this increase in import at low prices has led to idling of significant capacities of the domestic industry during the period of investigation;
- (d) though domestic industry has huge installed capacity, it is unable to increase its production of subject goods despite increase in domestic demand of the subject goods;
- (e) market share of the domestic industry has declined significantly.

and came to a preliminary conclusion that critical circumstances exist where delay in imposition of safeguard measures would cause irreparable damage to the domestic producers and recommended an increase in rate of duty of customs by 5 percent, for a period of 180 days, on imports of subject goods, originating in Malaysia and imported under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with rule 9 of the said Rules, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby increases the rate of duty of customs by 5 percent, on imports of subject goods for 180 days, originating in Malaysia and imported under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement by making the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.53/2011-Customs, dated the 1st July, 2011, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 499 (E), dated the 1st July, 2011, namely: -

In the said notification,

- (i) after Sl. No. 130 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“130A.	151190	All goods	50.0”;

(ii) after the Table, the following shall be inserted namely: -

“Provided that nothing contained in serial number 130 and entries relating thereto of the said table shall have effect upto and inclusive of the 2nd day of March 2020:

Provided further that nothing contained in serial number 130A and entries relating thereto of the said table shall have effect on or after the 3rd day of March 2020.”

[F. No. 354/132/2019-TRU]
RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 53/2011-Customs, dated the 1st July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 499 (E), dated the 1st July, 2011 and was last amended vide notification No. 84/2018-Customs, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1259 (E), dated the 31st December, 2018.